



सुविचार

सफलता कोई पहले से ही निर्मित
वर्स्तु नहीं इसे पाना पड़ता है।

प्रभात मन्त्र

तजा खबरों के लिए टेली

prabhatmantra.com

पृष्ठ 12 | मूल्य 4 रुपये

पोस्टल रजिस्ट्रेशन : आरएन /257/2021-23

मंगलवार

04.07.2023

RNI No. - JAHIN/2014/59110



ॐ तत्त्वं
एवं वाय

राजकीय श्रावणी मेला

में सभी श्रद्धालुओं और कांवरियों का

धार्मिक अभिनंदन और जोषार

भगवान भोलेनाथ सभी भक्तों
की मनोकामना पूर्ण करें



देमन्त सोरेन
मुख्यमंत्री, झारखण्ड

संपादकीय

राजभवन की गफलत

तमिलनाडु के राज्यपाल आर एन रवि ने अचानक जिस तरह से राज्य के एक मंत्री वी सेथिल बालाजी को बखास्त करने का आदेश दिया, वह सकते में डालने वाला है। हालांकि इसके ऊपरोड़ी ही देर बाद, संभवतः गृह मंत्रालय के सुझाव पर, राज्यपाल ने यह कहते हुए अपने उस आदेश पर अमल रुकवा दिया कि वह इस पर कानूनी राय लेना चाहते हैं। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। राज्यपाल का आदेश निकल चुका था, जिससे हत्रप्रभ राज्य सरकार को समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्योंकिसे हो गया? क्या वाकई राजभवन से मंत्रिमंडल की सलाह के बगैर ऐसा आदेश दिया जा सकता है? आदेश की पुष्टि होने के बाद मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने इस फैसले को सुनीम कोर्ट में चुनौती देने की बात कही। गनीमत रही कि गृह मंत्रालय ने मामले की गंभीरता को समझा और उसकी सलाह पर राज्यपाल ने अपने कदम पीछे खींच लिया। लेकिन यह सवाल रह ही गया कि

राज्यपाल केंद्र के प्रतिनिधि के तौर पर राज्य में होता है और कुछ खास स्थितियों को छोड़कर प्रशासनिक कार्यों में उसका कोई दखल नहीं होता। वह मंत्रिमंडल की सलाह पर ही फैसले करता है। यह व्यवस्था देश में शुरू से चली आ रही है। समय-समय पर कुछ जटिलताएं या अनिश्चितताएं समाने आती हैं, उस वजह से फैसले में या फैसले लेने की प्रक्रिया में गडबड़ियां होती हैं तो उनके निपटारे के लिए न्यायपालिका है, जो अपना काम बखूबी करती रही है। राज्यपाल की भूमिका को लेकर भी समय-समय पर आए सुप्रीम कोर्ट के तमाम फैसले हैं, जो किसी बड़ी गलतफहमी की गुंजाइश नहीं रहने देते। इसके बावजूद अगर तमिलनाडु में राज्यपाल कार्यालय से इस तरह की गलती हो जाती है तो संवंधित पक्षों के लिए यह चिंता की बात है।

गलतफहमी को गुजारिश नहीं रहने देते। इसके बावजूद अगर तमिलनाडु में राज्यपाल कार्यालय से इस तरह की गलती हो जाती है तो संवैधित पक्षों के लिए, यह चिंता की बात है। हालांकि राज्यपाल के फैसले पर विवाद का यह कोई पहला मामला नहीं है, अतीत में तमाम दलों की सरकारों के कार्यकाल में ऐसे विवाद सामने आते रहे हैं, लेकिन इस तथ्य से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि पिछले कुछ समय से खास तौर पर उन राज्यों के राज्यपालों की भूमिका पर लगातार सवाल उठ रहे हैं, जहां गैर-बीजेपी दलों का शासन है। ऐसे में केंद्र सरकार और सत्तारूढ़ दल को शायद इस समस्या पर ज्यादा गंभीरता से गौर करने की जरूरत है।

ਫੁਲ ਅਲੋਗ

अर इमला ह, कच्चा आम ह क्या
परेशान हैं टमाटर के ढामों पर
किसी इलाहाबादी आईएएस अफसर से पछिए तो वह कहेगा- ठीक

वैसा ही इश्क जैसा, अरहर की दाल में टमाटर-प्याज के तड़के का। तुअर दाल या येलो दाल भी बोलेंगे तो इस तड़के वाली दाल का स्वाद नहीं बदलने वाला। फिर भी जाने क्यों जबसे टमाटर सौं स्पष्टये किलो के पार पहुंचा है, तबसे एक घनयोरा राष्ट्र वाली मित्र रोजाना टमाटर के इतिहास को खोट रहे हैं। उनका कहना है कि भारतीयों को टमाटर जैसे लैटिन अमेरिकी फल या सब्जी से परहेज करना चाहिए, क्योंकि यह टमाटर फिलहाल अपने दामों से देश के आम लोगों की चटनी बनाए दे रहा है। टमाटर का इतिहास, भारतीय कलाइमेट में सहेत पर इसका प्रभाव और इसके साथ हो रहे जेनेटिक इनोवेशन से बिगड़े खाद्य की बात तो बाद में। पहला सवाल तो यह है कि टमाटर उगाने वाले किसान को अभी दो महीने पहले तक ही फसल के इतने कम दाम मिल रहे थे कि बेचारे सँडक पर फेंकने को मजबूर थे। दूसरी तरफ आम जनता है कि बेचारी सौं रुपये में एक किलो टमाटर खरीदने के बजाय दो किलो आम खरीदकर घर वापस चली आ रही है। यानी किसान को दाम नहीं मिल रहे और कस्टमर को टमाटर इतने महंगे पड़ रहे कि खरीदने की हिम्मत नहीं हो रही। अब सवाल यह है कि इस महंगाई का फायदा उठाने कौन रहा है। छोटे सब्जी वाले तक परेशान हैं, क्योंकि उन्हें खुद महंगा मिल रहा है और ग्राहकों का गुस्सा उन्हें झेलना पड़ रहा है। टमाटर के इस हाल पर धूमिल की मशहूर कविता याद आती है - 'एक आदमी रोटी बेलता है, एक आदमी रोटी खाता है, एक तीसरा आदमी भी है, जो न रोटी बेलता है, न रोटी खाता है, वह सिर्फ रोटी से खेलता है, मैं पूछता हूँ-यह तीसरा आदमी कौन है? मेरे देश की संसद मौन है।' धूमिल साहब के जमाने में कोई रोटी से खेल रहा था, आज टमाटर से खेल रहा है। इसलिए अब संसद, देश की सरकारें और शासन-प्रशासन के पास मौका है कि वह मौन न रहें। जानें कि वो बीचालिया कौन है, जो न टमाटर पैदा करता है और न खाता है, वह सिर्फ इसके दामों से खेलता है। बीच के इस आदमी को ढूँढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि आज टमाटर हो या प्याज, आलू हो या गेहूँ, यह बीच में रहकर खेलने वाला ही सबसे ज्यादा खा रहा है। अब वापस आते हैं टमाटर से जुड़े अतरंगी बिचारों पर। जैसे टमाटर का विदेशी होना। देश के लिए यह फिक्र बाली बात होनी ही चाहिए कि

जब राष्ट्रवाद का उभार अपने चरम पर हो तो देसी लोग सबसे ज्यादा चाउमिन और मोमे के ठेलों पर नजर आते हैं। जिनकी हालत थोड़ी बेहतर है वह खान मार्केट में जैपनीज, वियतनामी, कोरियन और इंडैलैयन फूद के लिए देर शाम रेस्टरंगों के बाहर लाइन में लगकर इंतजार करते हैं। टमाटर का महंगा होना और उसके लिए फिक्र मंद होना वार्कइ में कई बार लोगों के राष्ट्रवाद पर सवाल उठाता है। अरे भाई, कच्चा आम अपना है, इमली अपनी है। डालो न सब्जी में और चाहे बटनी बनाओ। दोनों अभी सस्ते भी हैं और हमारे शरीर के लिए टमाटर के मुकाबले कहीं ज्यादा फायदेमंद है। कई साल पहले नैशनल बॉटनिकल रिसर्च सेंटर में एक साइटिस्ट डॉ. पुष्पांगदन अपने मित्र थे। वह अक्सर समझाते थे कि भाई, टमाटर क्यों खाते हो? तीन-चार सौ साल पहले ही यह लैटिन अमेरिका, मैक्सिको और पुर्तगाल होते हुए भारत पहुंचा था। बाद में जब यह अंग्रेजों को भाया तो उन्होंने इसकी खेती शुरू करा दी। फिर पाकिस्तान से इधर आए सिंधी पंजाबी भाषियों ने आजादी के समय घ्याज-टमाटर के तड़कों से सरी दिल्ली में खुशबूफैला दी और यहां से उड़ी खुशबू सारे देश तक फैल गई। खैर जब फैली थी, तब फैल गई। काल, खंड और परिस्थितियों के हिसाब से शौक, स्वद और मिजाज सब बदलता है। प्रखर राष्ट्रवाद के इस दौर में विद्वानों का यह फर्ज बनता है कि वह राष्ट्रवादी सब्जियों और फलों की लिस्ट अलग से बनाए। उन्हें ही देसी माना जाए, जिनको अपने यहां खाए जाने का इतिहास कम से कम पांच हजार साल पुराना तो ही ही। इतिहास बदलने के इस दौर में इस दिशा पर भी काम हो। जो भी लोग विदेश से आए या अपने यहां ही उगाए जा रहे एजेंटिक फल-सब्जी खाते पाए जाएं, उन पर टैक्स भी लगा देना चाहिए, जैएसटी के साथ। इससे होने वाली आमदनी से देसी फल-सब्जी खानेवालों को सब्सिडी दी जा सकती है। वैसे भी, लैटिन अमेरिका से चले वहां के देसी टमाटर के स्वाद में इतना ज्यादा बदलाव हो चुका है कि क्या असली है और क्या नकली, इसका पता करना ही मुश्किल है। हमारे बचपन वाला टमाटर तो अब मिलता ही नहीं। इलाहाबाद में कमरा लेकर सिविलस की तैयारी करनेवालों को भी अपनी दाल का तड़का अब बदल ही लेना चाहिए। वह टमाटर अब रहा ही कहाँ,

ललित गर्ग

हमारी प्राचीन गुरुकुल परम्परा एवं
गुरुकुल संस्कृति ने महर्षि, तपसी,
राष्ट्रभक्त, चक्रवर्ती सम्प्राट और
जगद्गुरु तक के सुयोग्य महापुरुष
उपलब्ध कराए हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम
श्रीराम ने भी गुरु महिमा को सर्वोपि-
माना है। जनकपुरी में ऋषि
विश्वामित्र की सेवा इसका प्रमाण
है। भारतीय संस्कृति में गुरु आश्रय
रहित व्यक्ति को अत्यंत हेय माना
गया है। हमारे देश के ऋषि-महर्षि,
तीर्थकर और महात्मा गौतम बुद्ध,
महावीर जैसी दिव्य विभूतियों ने गुरु
पद से अपने उपदेशों से उदार भावन
स्थापित की। भौतिकवादी युग में
गुरु के प्रति आस्था में न्यूनता आई
है, जिसके परिणाम स्वरूप जीवन
अशांति, असुरक्षा और मानवीय
गुणों का अभाव हो रहा है।

निश्चित रूप से सारे घटनाक्रमों की वजह फ्रांस की पुलिस और वहाँ का असहिष्णु कानून है जेसकी वजह से देश हिंसा की आग में जल रहा है। ट्रैफिक नियम कथित रूप से अनुपालन न करने पर एक किशोर को जांच आड़ में गोली मार दी गई। कार्रवालक 17 वर्षीय किशोर नाहेल यम पर आरोप था कि उसने वाहन विकिंग के दौरान पुलिस पर रिवाल्वर तान दिया था। निश्चित रूप से इसकी जितनी आलोचना जाय वह कम है। दुनिया भर मानवीय और उसके अधिकार स्वरूपीर्पी होना चाहिए। मीडिया खबरों और उसके विश्लेषण रपता चलता है कि पुलिस अपनी कामाकारी छुपाने के लिए निर्दोष युवक पर इस तरह का आरोप लगाता है। नाहेल ने अगर ट्रैफिक नियम को तोड़ा था तो उसे दूसरे तरीके से भी सजा दी जा सकती थी। यह जुर्म इतना बड़ा नहीं था कि उसे गोली मार दी जाय। निश्चित रूप से पुलिस ने फ्रांस के लिए अपना कानून का दुरुपयोग किया है। गोली मारने की यह पहली घटना नहीं है इसके पूर्व भी कई लोग शकार हुए हैं। मीडिया में यह तभी सामने आए हैं कि पुलिस नस्लीय मानसिकता में भी बेगुनाही निशाना बनाती है।

नागरिक बोध

महिलाओं से आकाश छीनता पितृसत्ता विश्वास

पितृसं

पर मुख्य रूप से पुरुषों का वर्चस्व है। यह रूप से जीवन के विभिन्न पहलाऊं त्रै अधिकार, सामाजिक विशेषाधिकार, नियंत्रण संपत्ति पर नियंत्रण और राजनीतिक नेतृत्व वर्चस्व की एक प्रणाली है। महिलाओं के कई मायनों में स्पष्ट है, निजी और सार्वजनिक क्षेत्रों में, जहां महिलाओं को उन अधिकारों तक पहुंच से वंचित रखा जाता है, जिन लिए आसानी से उपलब्ध हैं। इसने अतीत प्रथाओं और महिलाओं की अधीनता समकालीन समय में भारत में मध्यवर्यायी महिलाओं की स्थिति में बाधा उत्पन्न की है। समाज में पितृसत्तात्मक दृष्टिकोण के कारण देखें तो पहले, महिलाओं को एक पुरुष

भारतीय

हसा का आग म सुलगता फ्रास

प्र०

लोग हिंसक और उग्र प्रदर्शन कर रहे हैं। मैंको सरकार हाशिए हैं। प्रदर्शन तेज होता जा रहा है। निश्चित रूप से सारे घटनाक्रम की वजह फ्रांस की पुलिस और वहां का असहिष्णु कानून है जिसकी वजह से देश हिंसा की आग में जल रहा है। ट्रैफिक नियमों का कथित रूप से अनुपालन न करने पर एक किशोर को जांच की आड़ में गोली मार दी गई। कार चालक 17 वर्षीय किशोर नाहेल एम पर आरोप था कि उसने वाहन चेकिंग के द्वारा गोली बोली थी। निश्चित रूप से इसकी जितनी आलोचना की जाय वह कम है। दुनिया भर में मानवीय और उसके अधिकार सर्वोंपरी होना चाहिए। मीडिया की खबारों और उसके विश्लेषण से पता चलता है कि पुलिस अपनी नाकामी छुपाने के लिए निंदोंपूर्वक पर इस तरह का आरोप मढ़ रही है। नाहेल ने अगर ट्रैफिक नियम को तोड़ा था तो उसे दूपर तरीके से भी सजा दी जा सकती थी। यह जुर्म इतना बड़ा नहीं था कि उसे गोली मार दी जाय। निश्चित रूप से पुलिस ने फ्रांस के लचीले कानून का दरुपयोग किया है। गोली मारने की यह पहली घटना नहीं है डम्सके पर्व भी कई लोग

सिकार हुए हैं। मीडिया में यह तथ्य भी सामने आए हैं कि पुलिस नस्लीय मानसिकता में भी बेगुनाहों को निशाना बनाती है। प्राप्त एक संप्रभु और लोकतान्त्रिक देश है। उसे ऐसे विवादित और कठोर कानून से बचना चाहिए। क्योंकि कानूनी आड़ में इसका दुरुपयोग किया जाता है। सरकार ट्रैफिक नियमों को इतना कठोर बनाकर लोकतान्त्रिक अधिकारों का दुरुपयोग कर रही है। अगर पुलिस के आरोप को ही सच मान लिया जाए। कि किशोर नाहेल ने ट्रैफिक नियमों का दुरुपयोग किया था तो पुलिस उसे सबक सिखाने के लिए दूसरे संवैधानिक अधिकार का भी प्रयोग किया जा सकता था। किसी की हत्या इसका समाधान नहीं था। देश के ट्रैफिक नियमों के मुताबिक उसकी गिरफतारी ही सकती थी। किशोर अधिनियम के तहत उसे जेल भी भेजा जा सकता था। उसे समझाने की कोशिश भी पुलिस कर सकती थी। बाहन चलाने पर प्रतिबंधित किया जा सकता था। लेकिन सिफक क्या जान लेना ही किसी कानून का संरक्षण है। भारत जैसे देश में अगर ऐसे कानून बना दिया जाए तो यहां पांच मिनट भी नहीं टिक सकते हैं। क्योंकि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतान्त्रिक देश है। लोकतंत्र में आम नागरिकों की सुरक्षा कैसे की जाती है यह भारत से बेहतर कोई नहीं जानता। यहां हर नागरिक को संवैधानिक अधिकारों के इतर जाकर उसके व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण किया जाता है।

नियंत्रित नहीं कर पा रही है। सरकार और पुलिस में शीतयुद्ध की अस्थित है लोग सड़क पर उतर कर उग्र और हिंसक प्रदर्शन कर रहे हैं। वाहनों को आग के वाले किया जा रहा है। किशोर की हत्या को लेकर लोगों में बेहद आक्रोश है। मानवाधिकार संगठन इस घटना की कड़ी निंदा कर रहे हैं। हालात को नियंत्रित करना सरकार के लिए मुश्किल हो रहा है। देश के कई हिस्सों में कम्फू नामा दिया गया है। नाहेल की हत्या करने वाले आरोपी पुलिसकर्मी ने गिरफ्तार कर लिया गया है। इस घटना को फ्रांस के राष्ट्रपति ने गंभीरता से लिया है। उन्होंने पुलिस की तीखी आलोचना की है। वैसे उनके बयान को लेकर पुलिस संगठनों ने तीखी वित्तिक्रिया व्यक्त की है और कहा है कि इससे पुलिस का मनोबल गया। लेकिन देश में बढ़ती हिंसा को रोकने की पहली नायिकता सरकार की है। आक्रोशित लोग प्रदर्शन के दौरान गरकारी इमारतें, पुलिस स्टेशन, स्कूलों और दूसरे संस्थानों को नशाना बना रहे हैं। पुलिस पर आरोप लगा रहे हैं कि ट्रैफिक नियमों की जांच के दौरान जानबूझकर निर्दोष किशोर को गोली मारी गई। हालांकि यह जांच विषय है। फ्रांस का गृह मंत्रालय भी पुलिस की करतूत पर बेहद नाराज है। दोषी पुलिस के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की घोषणा किया है। किशोर की मां मानिया इस घटना से बेहद दुखी है। क्योंकि उसका बेटा नाहेल इकलौती संतान थी। जिसे वह बेहद प्यार करती थी। घटना के दिन मां से लाड प्यार कर

हनकलाथा, लाकनएकघटबादगालाकाशकरबनगया। सघटनासेउसकीमांसदमेमै है। उसकाआरोपहैकिपुलिसनेगानवृक्षकरउसके बेटेकीहत्याकी। क्रांससरकारने2017मेंगोलीमारनेकेकानूनमेंडीलदेनेकाफैसलाकियाथा। अबसतरहकालचीलाकानूनउसीलिएभारीपड़रहा है। जबकि यसीदौरानमानवाधिकारसंगठनोंनेसरकारसेइसकानूनकोप्राप्तलेनेकाद्वावबनायाथा। क्रांसकीभीडियाकेमुताबिकबसेइसकानूनमेंसंशोधनहुआहैइसतरहकीघटनाएंतेजीबढ़ीहैं। बीबीसीकीएकरिपोर्टकेअनुसारअबतक13लोगराकरबनेहैं। पुलिसपरयहभीआरोपलगरहे हैंकिंगोलियांगलेऔरअरबकेमूललोगोंपरचलाईजातीहै। जिसकीजगहसेनिर्देशकिशोरकीजानगईहै। नाहेलकासंबंधभीवंसीसी-अल्जीरियामूलसेबतायागयाहै। क्रांससरकारकोसतरहकीघटनाओंकोरोकनेकेलिएआवश्यककदमदृढ़ठानेचाहिए। ट्रैफिकनियमोंमेंतत्कालसुधारकियाजानाचाहिए। वाहनोंकीचेकिंगकेलिएगोलीचलानेपरप्रतिबंधनगनचाहिए। क्रांसकेआमनागरिकअधिकारोंकाखुलीतरहसंरक्षणहोनाचाहिए। दुनियाभरमेंलोकतांत्रिकदेशमेंरहालमेंमानवीयअधिकारोंकासंरक्षणहोनाचाहिएऔरसेनिर्ममकानूनपररोकलगानेचाहिए। दोषीपुलिसकर्मीकोनिर्दोषकिशोरकीहत्याकेलिएकठोरदंडदियाजानाचाहिए।

समान नागरिक संहिता हकीकत बन हास्ये गंतिथान विराजित औं का बदा

हमारे संविधान निर्माताओं का बड़ा सम्मान होगा

की बरसों पु

साहता योग हककाकत बनता है तां इससे दश का आकाशकाण्ड हो पूरा नहीं होंगी बल्कि हमारे संविधान निर्माताओं की अपेक्षाएँ भी पूरी होंगी। हमारे संविधान निर्माताओं ने समान नागरिक संहिता का पक्ष लेते हुए इसे मूर्त रूप देने का जो दायित्व आने वाली सरकारें पर छोड़ा था, उस संकल्प को यदि मोदी सरकार सिद्ध करती है तो निश्चित ही यह हमारी संविधान सभा के सदस्यों का सम्मान भी होगा। देखा जाये तो संविधान सभा ने जो संवैधानिक प्रावधान किये थे, उन सभी का पालन देश आरम्भकाल से करता आ रहा है। लेकिन कुछ ऐसे मुद्दे भी थे जिस पर संविधान सभा में सहमति तो थी लेकिन उस पर फैसला करने का दायित्व भविष्य की सरकारों के लिए छोड़ दिया गया था। यह गौर करने योग्य बात है कि उस दायित्व को पूरा करने का साहस पहली बार कोई सरकार दिखा रही है।

समान नागरिक संहिता पर

विधि आयोग के समक्ष रोजाना देरों सुझाव आ रहे हैं। 14 जुलाई सुझाव और विचार भेजने की अंतिम तिथि है, तब तक यह संख्या लाखों में पहुँच सकती है। इसके अलावा, समान नागरिक संहिता को लेकर देश में गली-मोहल्लों से लेकर टीवी चैनलों की डिबेटों और राजनीतिक जनसभाओं के मंचों तक जो चर्चा और बहस का दौर चल रहा है वह दर्शा रहा है कि पूरा देश इस समय इस गंभीर मुद्दे पर मंथन कर रहा है। देखा जाये तो लोकतंत्र में किसी कानून के निर्माण में जितनी ज्यादा भागीदारी होगी वह कानून उतना ही सशक्त होगा। अभी जनता संभावित कानून को लेकर बहस कर रही है। जब

हमारे संविधान निर्माताओं ने समान नागरिक संहिता का पक्ष लेते हुए इसे मूर्त रूप देने का जो दायित्व आने वाली सरकारों पर छोड़ा था, उस संकल्प को यदि मोदी सरकार सिद्ध करती है तो निश्चित ही यह हमारी संविधान सभा के सदस्यों का सम्मान भी होगा। देखा जाये तो संविधान सभा ने जो संवैधानिक प्रावधान किये थे, उन सभी का पालन देश आरम्भकाल से करता आ रहा है। लेकिन कुछ ऐसे मुद्दे भी थे जिस पर संविधान सभा में सहमति तो थी लेकिन उस पर फैसला करने का दायित्व भविष्य की सरकारों के लिए छोड़ दिया गया था। यह गौर करने योग्य बात है कि उस दायित्व को पूरा करने का साहस पहली बार कोई सरकार दिखा रही है।

मसौदा प्रस्ताव सामने आयेगा दिखा रही है।
तब वह उसके लाभ हानि से जुड़े मुट्ठों पर बहस करेगी और जनभावना को ध्यान में रखते हुए संसद में संसद भी प्रस्तावित विधेयक पर बहस करेगा। इसलिए जो लाग यह भ्रम फैलाने का अभियान चला रहा है कि समान नागरिक संहिता को थोपा जा रहा है उन्हें देखना चाहिए कि जबकि सीकानून को बनाने से पहले संपूर्ण प्रक्रिया का पालन किया जा रहा है तब वह थोपा हुआ कैसे हो सकता है? इसके अलावा, समान नागरिक संहिता के विरोध में तमाम तरह के तर्क दे रहे, समान नागरिक संहिता आने पर तकान आने की चेतावनी दे रहे और समान नागरिक संहिता आने पर धर्मिक आधार पर विभाजन बढ़ाने

की बात कह रहे होंगों को देखना चाहिए कि यह देश के लिए नई चीज़ नहीं है। गोवा में आजादी के बाद से ही समान नागरिक संहिता लागू है। क्या किसी ने सुना है कि वहाँ पर धर्मिक आधार पर भेदभाव होता है? क्या किसी ने सुना है कि गोवा में समान नागरिक संहिता की वज्र से अल्पसंख्यकों को किसी भी प्रकार की मुश्किलों का सामना करना पड़ा? क्या किसी ने सुना है कि समान नागरिक संहिता की वज्र से किसी को अनावश्यक लाभ या किसी को नुकसान हुआ? जाहिर है इन सभी प्रश्नों का उत्तर नहीं मौं ही होगा। इसलिए जब हमारे समक्ष गोवा जैसा जाचा परखा और खरा उदाहरण हो तो समान नागरिक संहिता का विरोध करना सिर्फ़ 'राजनीति' से प्रेरित कदम ही लगता है। इसके साथ ही हमें यह भी देखना चाहिए कि दुनिया के कई देशों में पहले से ही समान नागरिक कानून हैं। साथ ही यह भी ध्यान रखना चाहिए कि उच्चतम न्यायालय की ओर से भी इस संबंध में कानून लाने के लिए सरकार को कहा जा चुका है। इसलिए समय आ गया है कि इस मुदे को टालने की बजाय इसका हल निकलना चाहिए ताकि आने वाली पीढ़ियों को उन राजनीतिक विवादों को नहीं झेलना पड़े जिसका आज की पीढ़ी ने समान किया या कर रही है। दुनिया जब तेजी से आगे बढ़ रही है, ऐसे में हम पीछे नहीं छूट जायें, इसके लिए जरूरी है कि देश के विकास और एकता को बाधित करने वाले दशकों पुराने मुदों का हल जल्द से जल्द निकाला जाये ताकि सरकार पुरानी दुश्वारियों को दूर करने में ऊर्जा लगाने की बजाय देश के



रात्री में मदीरा लाउंज एंड बार का हुआ भव्य शुभारंभ

रात्री (ग्रामत मंत्र संवाददाता): राजधानी के हरमू, असोरो में रविवार को

मदीरा लाउंज एंड बार का भव्य शुभारंभ किया गया। इस लाउंज एंड बार की शुरुआत मदीरा लाउंज एंड बार के संचालक अधिकारीक आनंद ब व्यवसाय गहुल राज द्वारा संयुक्त रूप से फैटी काटक को गई। कार्यक्रम को सम्मोहन करते



हुए मुख्य अंतिथि सासद संजय सेठ ने मदीरा लाउंज एंड बार के सभी कर्मचारियों को अपनी सुभकामानार्थी दी और कहा कि रात्री में लोगों के खाने - पीने के लिए यह उपयुक्त स्थान सबित होगा। अपने सम्मोहन में मदीरा लाउंज एंड बार के संचालक अधिकारीक आनंद ने बताया कि मदीरा लाउंज एंड बार रात्री का एकमात्र ऐसा ब्रांड है जिसकी शाखा विदेश में है। इस बार में 15 जुलाई तक सभी ग्राहकों को बीस प्रतिशत तक सभी सर्विसेज पर छूट दी जाएगी। यह लाउंज एंड बार सभी तरह के ग्राहकों का खाल रखने हुए बनाया गया है। उन्होंने कहा कि यहां पर बेस्ट कल्चर्स की सारी डिस्ट्रिक्शन के साथ विभिन्न वेयरेटेज की ड्रिक्स उपलब्ध है। इस लाउंज एंड बार की एक अलग ही व्यवहार की तुला देती है। यहां पर भव्य पार्किंग के साथ ही अन्य सभी तरह की सुविधाएँ ग्राहकों के लिए उपलब्ध हैं। कार्यक्रम में गायक एंड सिंगरी की दीम द्वारा लाइव परफॉर्मेंस दिया गया जिसका शहरावासियों ने जमकर लुक़ उठाया।

सहारा एवं सोसाइटीज ने निवेशकर्ताओं को तथ्यों से अवगत कराया

रात्री (ग्रामत मंत्र संवाददाता): सहारा एवं सोसाइटीज ने एक वक्तव्य जारी कर निवेशकर्ताओं को अवगत कराया कि झारखण्ड राज्य में 03 सोसाइटी कार्यरत हैं, जिनका नाम सहारा क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, हमारा इडिया क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड एवं सहाराय यूनिवर्सल मल्टीप्रॉपर्टेटर को-ऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड है। उक्त तीनों सोसाइटी सेन्ट्रल रजिस्ट्रर ऑफ को-ऑपरेटिव सोसाइटीज कृषि मंत्रालय (उनमें सहारा एवं सोसाइटी मंत्रालय) भारत के सभी अधिकारियों तथा सेन्ट्रल रजिस्ट्रर ऑफ को-ऑपरेटिव सोसाइटीज कृषि मंत्रालय के उपनियमों में प्रदत्त शक्तियों के अनुरूप निवेशित किया गया है। निवेश प्राप्त कर्मनी सहारा एवं अन्य कर्मनीज की परिधि में आती है उक्त दोनों कंपनियों पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 21.11.2013 के संदर्भ में सहारा एवं अन्य कर्मनीज की चलन-अचल सम्पत्तियों के हस्तान्तरण/व्यवहार पर अनुमति न होने तो दोपारन संशोधित आदेश दिनांक 03.08.2016 के संदर्भ में अत्र सम्पत्तियों के विक्रय करने की अनुमति होने पर भी सम्पत्तियों को बेकर/गिरवी रखकर अथवा किसी अन्य व्यवस्था से प्राप्त धनराशि को सहारा-सेवी एकाउंट में जमा करने के सम्बन्ध में अन्य सेवा दिया गया है। सहारा प्रबन्धन एवं सोसाइटी प्रबन्धन द्वारा समय-समय पर अपनी इन परिवर्थितियों को सभी समानित जन प्रतिनिधियों, समानित प्रशासनिक अधिकारियों, समानित पुलिस अधिकारियों एवं अपने समानित निवेशकों को पत्र एवं समाचार भरते के माध्यम से अवगत कराया जाता रहा है।

सांसद ने अरगुड़ा महाप्रबंधक को छोटका व मंडलायुमा में डीप बोरिंग लगाने की अनुशंसा की
सिरका (ग्रामत मंत्र संवाददाता): सांसद हजारीबाग जारी सिन्हा के द्वारा सीसोएल अरगुड़ा महाप्रबंधक को अनुशंसा पत्र भेजा गया है। जिसमें सीसोएल अरगुड़ा के तातत छोटका चुक्का में विस्तार स्थित कल्पाणा ट्रूट कार्यालय के सभी मरीन सहित डीप बोरिंग व मिलानाचुक्का के चाढ़नी चौक में भी मरीन सहित डीप बोरिंग लगाने के बारे में कहा गया। बताएं कि इससे पूर्व भाजपा एसी मोर्चा के जिला समग्र उपाध्यक्ष प्रेम रविदास ने बीते 21 जून को समस्याओं के लेकर सांसद को पत्र सौंपा था।

उपायुक्त ने सुनी जनता की समस्याएं
मंडलायुमा में डीप बोरिंग लगाने की अनुशंसा की

सिरका (ग्रामत मंत्र संवाददाता): सांसद हजारीबाग जारी सिन्हा के द्वारा अरगुड़ा महाप्रबंधक को अनुशंसा पत्र भेजा गया है। जिसमें सीसोएल अरगुड़ा के तातत छोटका चुक्का में विस्तार स्थित कल्पाणा ट्रूट कार्यालय के सभी मरीन सहित डीप बोरिंग व मिलानाचुक्का के चाढ़नी चौक में भी मरीन सहित डीप बोरिंग लगाने के बारे में कहा गया। बताएं कि इससे पूर्व भाजपा एसी मोर्चा के जिला समग्र उपाध्यक्ष प्रेम रविदास ने बीते 21 जून को समस्याओं के लेकर सांसद को पत्र सौंपा था।

कार्यालयः— जिला अभियंता, लातेहार।
सूचना
अद्योहस्ताक्षरी कार्यालय द्वारा आमंत्रित अति अल्पकालीन निविदा संख्या—13 / 2023–24 प्रकाशित करायी गयी थी जिसका PR. No 300779 Rural Development (23-24)D है। उक्त आमंत्रित निविदा को अगले आदेश तक स्थगित किया जाता है।

जिला अभियंता, लातेहार।

PR 301230 Rural Development(23-24)D

OFFICE OF THE ELECTRICAL EXECUTIVE ENGINEER
ELECTRIC WROKS DIVISION, RANCHI
Energy Department, Govt of Jharkhand.

Very Short Notice Inviting e-quotation

Notice No-Energy/EWD/Ranchi/23/23-24

Quotation through e-tender are invited for rate of Item/materials annexed as Annexure-1 for framing estimate from Reputed Manufacturers/ authorize agency/ Departmental registered contractor. The Item/Material Rate conforming to specifications shall be submitted online in the website [Https://jharkhandtenders.gov.in](https://jharkhandtenders.gov.in). Details are available on the above e-tender portal. The quotation may download the documents from the website and quote their rate online from 08/07/2023 at 11:00 hrs. to 13/07/2023 at 14:00 hrs. The quotation will be opened on 14/07/2023 at 14:00 Hours.

The quotation is invited to ascertain and assess the Item/Material Rate at par with lowest market rate for framing of Estimate.

Electrical Executive Engineer

PR 301261Energy(23-24)D

Electric Works Division, Ranchi.

बरही थाना के गश्तीदल के पुलिस के द्वारा मारपीट में पत्रकार घायल, रेफर

प्रभात मंत्र संवाददाता

बरही (हजारीबाग): रविवार रात्री बरही में एक पत्रकार के साथ मारपीट का मामला प्रकाश में आया है। बाताया जाता है कि बरही थाना के गश्तीदल की पुलिस ने बरही के पत्रकार सोमानाथ वर्मा के साथ मारपीट की। जिसमें पुलिस की मारपीट की बाबत आनंद वर्मा से बोलता था कि वर्मा के साथ वर्मा के दो बच्चे वर्मा के बाथरूम में लोगों के खाने - पीने के लिए यह उपयुक्त स्थान सबित होगा। अपने सम्मोहन में मदीरा लाउंज एंड बार के संचालक अधिकारीक आनंद व व्यवसाय गहुल राज द्वारा संयुक्त रूप से फैटी काटक को गई। कार्यक्रम को सम्मोहन करते



निकला है। मारपीट के दो बच्चे मौजूद रहे। जिसमें एक बच्चा बरही का गश्तीदल की पुलिस के साथ वर्मा के दो बच्चे वर्मा के बाथरूम में लोगों के खाने - पीने के लिए यह उपयुक्त स्थान सबित होगा। अपने सम्मोहन में मदीरा लाउंज एंड बार के संचालक अधिकारीक आनंद वर्मा एवं व्यवसाय गहुल राज के लिए उपयुक्त है। इस बार में 15 जुलाई तक सभी ग्राहकों को बीस प्रतिशत तक सभी सर्विसेज पर छूट दी जाएगी। यह लाउंज एंड बार सभी तरह के ग्राहकों का खाल रखने हुए बनाया गया है। उन्होंने कहा कि यहां पर बेस्ट कल्चर्स की साथ विभिन्न वेयरेटेज की ड्रिक्स उपलब्ध है। इस लाउंज एंड बार की एक अलग ही व्यवहार की तुला देती है। यहां पर भव्य पार्किंग के साथ ही अन्य सभी तरह की सुविधाएँ ग्राहकों के लिए उपलब्ध हैं। कार्यक्रम में गायक एंड सिंगरी की दीम द्वारा लाइव परफॉर्मेंस दिया गया जिसका शहरावासियों ने जमकर लुक़ उठाया।

सहारा एवं सोसाइटीज ने निवेशकर्ताओं को तथ्यों से अवगत कराया

अवगत कराया

रात्री (ग्रामत मंत्र संवाददाता): सहारा एवं सोसाइटीज ने एक वक्तव्य जारी कर निवेशकर्ताओं को अवगत कराया कि झारखण्ड राज्य में 03 सोसाइटी कार्यरत हैं, जिनका नाम सहारा क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, हमारा इडिया क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड एवं सहाराय यूनिवर्सल मल्टीप्रॉपर्टेटर को-ऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड है। उक्त तीनों सोसाइटी सेन्ट्रल रजिस्ट्रर ऑफ को-ऑपरेटिव सोसाइटीज कृषि मंत्रालय (उनमें सहारा एवं सोसाइटी मंत्रालय) भारत के प्राविधिक उत्तराधिकार में पंजीकृत हैं। सोसाइटीज ने अपने सदस्यों से जमा जी गयी धनराशि को अधिकारियों तथा अधिकारियों के उपर्युक्त व्यवस्था से सहारा एवं अन्य सभी सम्पत्तियों के अनुरूप निवेशित किया गया। निवेश प्राप्त कर्मनी सहारा एवं अन्य कर्मनीज की परिधि में आती है उक्त दोनों कंपनियों पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 21.11.2013 के संदर्भ में सहारा एवं अन्य कर्मनीज की चलन-अचल सम्पत्तियों के हस्तान्तरण/व्यवहार पर अनुमति न होने तो दोपारन संशोधित आदेश दिनांक 03.08.2016 के संदर्भ में अत्र सम्पत्तियों के विक्रय करने की अनुमति होने पर भी सम्पत्तियों को बेकर/गिरवी रखकर अथवा किसी अन्य व्यवस्था से प्राप्त धनराशि को सहारा-सेवी एकाउंट में जमा करने के सम्बन्ध में अन्य सेवा दिया गया है। सहारा प्रबन्धन एवं सोसाइटी प्रबन्धन के उपर्युक्त व्यवस्था से सहारा एवं सोसाइटीज के अनुरूप निवेशित किया गया है। जिसका शहरावासियों ने जमकर लुक़ उठाया।

सहारा एवं सोसाइटीज ने निवेशकर्ताओं को तथ्यों से अवगत कराया

प्रभात मंत्र संवाददाता

बरही (हजारीबाग): रविवार रात्री बरही में एक पत्रकार के साथ मारपीट का मामला प्रकाश में आया है। बाताया जाता है कि बरही थाना के गश्तीदल की पुलिस ने बरही के पत्रकार सोमानाथ वर्मा के साथ मारपीट की। जिसमें पुलिस की भारी बातों से बोलता था कि वर्मा के साथ वर्मा के दो बच्चे वर्मा के बाथरू

